

बलूचिस्तान में संघर्ष ट्रेन हाइजैकिंग

बलूचिस्तान में ट्रेन हाइजैकिंग ने इस क्षेत्र के संघर्ष को उजागर कर दिया है। बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस की हालिया हाइजैकिंग बलूच स्वतंत्रता के लिए दशकों लंबे संघर्ष में एक और घातक प्रकरण है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी-बीएलएफ़ द्वारा किए गए हमले से पाकिस्तान के सबसे बड़े, पर सर्वाधिक अनदेखी के शिकार प्रांत में विद्रोह में वृद्धि उजागर की है। हालांकि, अपहरणकर्ताओं के खिलाफ पाकिस्तानी सेना को त्वरित कार्रवाई से तत्काल यह संकट दूर हो गया है, पर यदि समस्या का कारण बनने वाली कठिनाइयाँ दूर न की गईं तो वे बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन को शक्ति देती रहेंगी। 11 मार्च को सशस्त्र विद्रोहियों ने ब्रेक्टा से पेशावर जाने वाली पैसंजर ट्रेन जाफ़र एक्सप्रेस पर निशाना लगाया। बीएलएफ़ ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा कथित रूप से अपहरण कर जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों और लोगों की रिहाई की मांग की है। पाकिस्तानी सेना ने बचाव के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू की। इस सफल कार्रवाई से बलूचिस्तान में खराब होती सुरक्षा स्थिति तथा अलगाववादी समूहों की बढ़ी हुई हिम्मत स्पष्ट होती है। यह हाइजैकिंग कोई अलग-थलग घटना न होकर स्वाशासन की खोज में बलूच जनता के लंबे संघर्ष की निरंतरता है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध, पर ऐतिहासिक रूप से हाशियाकृत बलूचिस्तान में 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के बाद से अनेक विद्रोह हुए हैं। इस टकराव की जड़ें बलूचों द्वारा पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना द्वारा दिए कथित धोखे में निहित हैं। विभाजन के समय कलात की देशी रियासत ने स्वतंत्रता का रास्ता चुना जो वर्तमान बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा थी। लेकिन 1948 में पाकिस्तान के दबाव तथा अंतरराष्ट्रीय समर्थन न मिलने के कारण कलात का जबरन अधिग्रहण कर लिया गया। इससे अंग्रेजों के खिलाफ भारी गुस्ता पैदा हुआ जिसके चलते सशस्त्र विद्रोह हुआ जो पिछले दशकों में अनेक रूपों में उभर कर सामने आता रहा है। सोना, तांबा और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। बलूच राष्ट्रवादियों का तर्क है कि केन्द्र सरकार क्षेत्र को संपदा का दोहन करती है और स्थानीय जनता को कोई लाभ नहीं मिलता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे-सीपीईसी ने तनाव और बढ़ा दिया है क्योंकि बलूच विद्रोही चीनी निवेशों और दौलतानत परियोजनाओं को स्थानीय समस्याओं को संबोधित किए बिना उनकी जमीन पर पाकिस्तान के बढ़ते नियंत्रण का माध्यम मानते हैं। व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों ने निराशा को और बढ़ावा दिया है जिनमें एकटिविस्टों और नागरिकों को जबरन गायब कर उनकी न्यायेतर हत्यायें शामिल हैं। पाकिस्तान राज्य ने अक्सर कठोर सैनिक कार्रवाइयों की हैं जिससे विद्रोह और व्यापक हुआ है। हालांकि, पिछले वर्षों में बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं, पर हालिया घटनायें इसके तेज होने का संकेत देती हैं। बीएलए तथा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट-बीएलएफ जैसे अन्य संगठनों ने सुरक्षा बलों, सरकारी दौलतानत संरचनाओं तथा सीपीईसी से जुड़ी परियोजनाओं पर हमले तेज किए हैं। पाकिस्तान में कार्यरत चीनी नागरिकों पर लक्षित हमलों से विदेशी निवेशों को अस्थिर करने तथा पाकिस्तान पर दबाव डालने की रणनीति स्पष्ट होती है। जाफ़र एक्सप्रेस की हाइजैकिंग विद्रोहियों की विकसित होती रणनीतियों तथा बढ़ती भयंकरता की प्रतीक है। सिविलियन ढाँचों पर निशाना लगा कर तथा बंधक बना कर बीएलएफ़ ने अपनी क्षमता प्रदर्शित कर दी है कि वह बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों कर सकता है। इससे अलगाववादी आंदोलन की मजबूती का संकेत मिलता है। केवल पाकिस्तानी सैनिक प्रतिक्रिया से बलूचिस्तान में विद्रोह समाप्त नहीं होगा। इस प्रांत में व्याप्त राजनीतिक अलगाव, आर्थिक हाशियाकरण तथा मानवाधिकार उल्लंघनों जैसे मूल कारणों को संबोधित करना दीर्घकालीन समस्या समाधान हेतु जरूरी है। बलूचिस्तान में जारी संघर्ष नस्ली व क्षेत्रीय शिकायतों को अनदेखी का परिणाम है। बिना सशस्त्र संवाद और राजनीतिक समाधानों के पाकिस्तान के सर्वाधिक संसाधन संपन्न, पर अस्थिर प्रांत में राजनीतिक अस्थिरता का खतरा और बढ़ जाएगा। हालिया ट्रेन हाइजैकिंग से भले ही निपट लिया गया हो, पर बलूच विद्रोह अभी समाप्त नहीं हुआ है।

मोदी की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही मुटापे तथा तेल के अत्यधिक उपयोग से निपटने की पहल की है। इससे रोग निवारक स्वास्थ्यरक्षा तथा भोजन में सुधार की आवश्यकता स्पष्ट होती है।



विश्वरूपा भट्टाचार्या
(लेखिका, राज्यसभा सचिवालय से संबद्ध हैं)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल में मुटापे से मुकाबला करने तथा तेल के अत्यधिक उपभोग से बचने की पहल की है। इस पहल ने पूरे देश में स्वास्थ्य और पोषण पर चर्चा छेड़ दी है। इस अभियान से रोग निवारक स्वास्थ्यरक्षा तथा भोजन में परिवर्तनों का महत्व स्पष्ट किया है जो भारत में मुटापे के बढ़ते संकट से निपटने के लिए जरूरी हैं। दुनिया भर में मुटापा खतरनाक रूप से बढ़ने की प्रवृत्ति को देखते हुए यह पहल बहुत सामर्थिक और जरूरी है। इसे स्वास्थ्यरक्षा पेशेवरों, खिलाड़ियों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन का व्यापक समर्थन मिल रहा है।



रूप से जल्दी पकाने वाले तत्वों, खाने के नमक में खड़िया, मसालों में नकली रंग, मछलियों में फार्मेलीन, चाय में लोहे का बुरादा या रंगी पत्तियाँ, चावल और गेहूँ में सिंथेटिक व्हाइटनर, खड़िया या सोपस्टोन तथा दालों में लेड क्रोमेट की मिलावट पाई गई है। शहरी क्षेत्रों में आरामतलब जीवनशैली तथा अस्वास्थ्यकर भोजन के कारण यह संख्या और अधिक है। अब हम सभी जानते हैं कि मुटापे से मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कुछ किस्म के कैंसरों का खतरा बढ़ जाता है। इन बीमारियों से भारत की स्वास्थ्यरक्षा व्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मुटापा एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य संकट है और भारत भी अब तेजी से पश्चिमी देशों में व्याप्त मुटापे की दर के निकट पहुंचता जा रहा है। लेकिन जीवनशैली परिवर्तनों के माध्यम से मुटापे की समस्या का मुकाबला करने के साथ ही ज्यादा महत्वपूर्ण तात्कालिक चिन्ता खाद्य पदार्थों में मिलावट की चुनौती का सामना करना है। 2018-19 में 'फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी आफ इंडिया'-एफएसएसआई ने पता लगाया कि भारत में मिलावट के कारण खाद्य पदार्थों के लगभग एक तिहाई परीक्षित नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरने में विफल रहे। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि खाद्य पदार्थों में खतरनाक तत्वों की मिलावट हो रही है। उदाहरण के लिए, दूध में यूरिया, स्टार्च तथा डिटर्जेंट, फलों में सिंथेटिक रंगों और कृत्रिम

वास्तव में खाद्य पदार्थों में व्यापक मिलावट सर्वोत्तम स्वास्थ्य-सचेतन प्रयासों को नुकसान पहुंचाती है। इससे ग्राहक अच्छा खाने के इरादे के बावजूद हानिकारक तत्वों के शिकार हो जाते हैं। रोजमर्रा के भोजन में हानिकारक रसायनों की उपस्थिति फलों व सब्जियों से लेकर डेरी व स्टेपल उत्पादों तक है जो स्वास्थ्य

मिल जाता है। यदि इस प्रवृत्ति पर लगाम न लगाई गई तो आर्गेनिक खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा और हम फिर से पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अतीत में अनेक सफल अभियानों को जन्म दिया है। इनमें 'स्वच्छ भारत अभियान' तथा 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के माध्यम से योग को प्रोत्साहित करना शामिल है। इनसे सार्वजनिक सहभागिता को लामबंद करने में मोदी की क्षमता प्रदर्शित हुई है जो सार्थक परिवर्तन का कारण बनी है। उम्मीद है कि मुटापे से लड़ने के लिए उनका नवीनतम अभियान भी जनता के साथ मजबूती से जुड़ जाएगा। लेकिन जहां उनकी पिछली पहलों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा वैश्विक स्वास्थ्य प्रवृत्तियों को सफलतापूर्वक प्रभावित किया है, वहीं मुटापे के खिलाफ नवीनतम अभियान का सार्थक प्रभाव केवल तभी अनुभव किया जा सकेगा जब खाद्य पदार्थों में मिलावट के मुद्दे से सफलतापूर्वक निपटा जा सके। मुटापे से मुकाबले में खाद्य पदार्थों में मिलावट सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि जब भारतीय स्वास्थ्यवर्धक विकल्प चुनें तो उनको सचमुच सुरक्षित और पोषक भोजन मिले। मुटापे से मुकाबला तथा खाने के तेल के अत्यधिक उपयोग को घटाने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अभियान भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वास्तव में खाद्य पदार्थों में व्यापक मिलावट सर्वोत्तम स्वास्थ्य-सचेतन प्रयासों को नुकसान पहुंचाती है। इससे ग्राहक अच्छा खाने के इरादे के बावजूद हानिकारक तत्वों के शिकार हो जाते हैं। रोजमर्रा के भोजन में हानिकारक रसायनों की उपस्थिति फलों व सब्जियों से लेकर डेरी व स्टेपल उत्पादों तक है जो स्वास्थ्य पर गंभीर जोखिम का कारण है। प्रधानमंत्री के पहले के अभियानों ने सफल व्यावहारिक परिवर्तन पैदा किए हैं और उनका मुटापा-विरोधी अभियान भी ऐसा ही कर सकता है। लेकिन इसकी सफलता खाद्य सुरक्षा विनियमनों के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर है जिनमें मिलावट के बारे में जन जागरूकता तथा सचमुच स्वास्थ्यवर्धक भोजन तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। नियामक ढांचा मजबूत करे खाद्य मिलावट के लिए कठोर दंड सुनिश्चित करे तथा सुस्पष्ट आर्गेनिक व्यवहारों का प्रयोग ये कर्मियाँ दूर कर सकते हैं।

चार दिवसीय कार्य सप्ताह की अवधारणा

“
भारत के श्रम बाजार में अलग-अलग जटिलताएं हैं, जिससे चार दिवसीय कार्य सप्ताह एक तत्काल प्राप्त करने योग्य समाधान की तुलना में एक आकांक्षा अधिक बन गया है।
”

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, जो भारत के लगभग 90 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देती है, पारंपरिक रोजगार प्रतिमानों से परे काम करती है। कृषि मजदूर, छोटे व्यवसाय के मालिक और दैनिक वेतन भोगी आम तौर पर एक निश्चित समय-सारिणी के बजाय मांग के आधार पर काम करते हैं। ऐसे श्रमिकों के लिए, चार दिवसीय कार्य सप्ताह का कोई महत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी कमाई सीधे काम किए गए घंटों की संख्या से जुड़ी होती है। इसके विपरीत, भारत के विस्तारित सेवा और प्रौद्योगिकी खाद्य संकुचित कार्य सप्ताह के साथ प्रयोग करने के लिए बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। कुछ ई-कॉमर्स संगठनों ने पहले ही चार-दिवसीय कार्य सप्ताह का परीक्षण किया है, जिसमें कर्मचारियों की संतुष्टि और उत्पादकता में आशाजनक परिणाम सामने आए हैं। हालांकि, ये मानक के बजाय अपवाद बने हुए हैं। भारत में काम की सांस्कृतिक धारणाएं एक और महत्वपूर्ण बाधा प्रस्तुत करती हैं। यह गहरी जड़ जमाई हुई मान्यता कि लंबे घंटे प्रतिबद्धता और समर्पण को दर्शाते हैं,

कार्य सप्ताह को कम करने के प्रति प्रतिरोध को बढ़ावा देती है। यह सांस्कृतिक मानसिकता बताती है कि भले ही नीतियाँ बदल जाएँ, लेकिन दृष्टिकोण बदलने में काफी समय लग सकता है। आधारभूत संरचना की चुनौतियाँ चार-दिवसीय कार्य सप्ताह की व्यवहार्यता को और जटिल बनाती हैं। अपर्याप्त परिवहन नेटवर्क और शहरी भीड़भाड़ के कारण कई भारतीय कर्मचारी लंबी यात्राएँ करते हैं। परिणामस्वरूप, संकुचित कार्य शेड्यूल के साथ भी, अवकाश और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए उपलब्ध वास्तविक समय सीमित रह सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद, भारत में चार-दिवसीय कार्य सप्ताह शुरू करने की दिशा में मार्ग तलाशने के लिए आकर्षक कारण हैं। शोध संभावित लाभों का सुझाव देते हैं, जिसमें कम बर्नआउट, कम अनुपस्थिति और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य-कारक शामिल हैं जो वर्तमान में भारतीय नियोक्ताओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कार्यस्थल मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं। क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण सबसे व्यवहार्य मार्ग प्रदान कर सकते हैं। ज्ञान-गहन उद्योगों में पायलट कार्यक्रम परीक्षण के आधार के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे सफल मॉडलों को धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे कार्यक्रमों को अपनाने के इच्छुक व्यवसायों के लिए सरकारी प्रोत्साहन इच्छुक व्यवसायों के लिए सरकारी प्रोत्साहन के रूप में देखने के बजाय, भारत इसे अधिक अनुपस्थिति और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य-कारक शामिल हैं जो वर्तमान में भारतीय नियोक्ताओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कार्यस्थल मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं।

महामारी ने पहले ही भारत सहित दुनिया भर में कार्य व्यवस्था को नया रूप दे दिया है। दूरस्थ और हाइब्रिड कार्य मॉडल ने उत्पादकता आवश्यकता आवश्यक रूप से शारीरिक उपस्थिति या कठोर शेड्यूल पर निर्भर नहीं है। दृष्टिकोण में यह बदलाव कार्यस्थल नवाचारों के लिए अवसर पैदा करता है, जिसमें संकुचित कार्य सप्ताह भी शामिल है। चार दिवसीय कार्य सप्ताह को लागू करने में फायदा है, बढ़ते सेवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र इसकी व्यवहार्यता के लिए परीक्षण का आधार प्रदान करते हैं। बुनियादी ढांचे की सीमाएं और गहरी जड़ें जमाए गए कार्य परंपराएं व्यापक रूप से अपनाने में देरी कर सकती हैं, लेकिन पायलट कार्यक्रम और सरकारी प्रोत्साहन धीरे-धीरे स्वीकृति को बढ़ावा दे सकते हैं। महामारी ने पहले ही कार्यालयन एक दूर का लक्ष्य हो सकता है, विशिष्ट क्षेत्रों में चयनात्मक अपनाने से व्यापक स्वीकृति के लिए आधार तैयार हो

सकता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे विकसित होता रहता है। भारत में कार्य सप्ताह सुधार की यात्रा लंबी, सांस्कृतिक रूप से जटिल और देश के आर्थिक परिदृश्य से निकटता से जुड़ी होगी। हालांकि, बातचीत शुरू करना सही दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। चार दिवसीय कार्य सप्ताह भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है। जबकि इसकी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक धारणाएं बाधाएं खड़ी करती हैं, बढ़ते सेवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र इसकी व्यवहार्यता के लिए परीक्षण का आधार प्रदान करते हैं। बुनियादी ढांचे की सीमाएं और गहरी जड़ें जमाए गए कार्य परंपराएं व्यापक रूप से अपनाने में देरी कर सकती हैं, लेकिन पायलट कार्यक्रम और सरकारी प्रोत्साहन धीरे-धीरे स्वीकृति को बढ़ावा दे सकते हैं। महामारी ने पहले ही कार्यालयन एक दूर का लक्ष्य हो सकता है, विशिष्ट क्षेत्रों में चयनात्मक अपनाने से व्यापक स्वीकृति के लिए आधार तैयार हो

आप की बात

राष्ट्र-विरोधी हरकत

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के बजट के लोगों के रूप में भारतीय रुपए के आधिकारिक प्रतीक चिह्न के स्थान पर तमिलनाडु भाषा में प्रस्तुत करने की हिमाकत की है। यह आग में पेट्रोल डालने वाली हरकत है। संविधान के अनुसार देश में मौद्रिक नियंत्रण पूर्णतः केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए यह हरकत राष्ट्र-विरोधी है। भाषावाद की भड़काऊ राजनीति को विभाजन की दह तक बढ़ाने का यह निंदनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री स्टालिन भले ही आगामी चुनाव में वोट पाने के लिए यह ओझी हरकतें कर रहे हों, मगर यह संघीय राष्ट्र पर प्रहार है। केन्द्र को कठोर नियम जारी करने चाहिए ताकि राष्ट्रीय प्रतीकों में

सभी भाषाओं का सम्मान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने पहले केंद्र की शिक्षा में त्रिभाषा-अंग्रेजी, हिंदी व स्थानीय भाषा फ़र्मूले को योजना का विरोध किया और अब उन्होंने बजट में रूपये के हिंदी चिह्न के स्थान पर तमिल भाषा के चिह्न का उपयोग करके विरोध जताया। कोई भी भाषा बातचीत और भावना से एक-दूसरे को अवगत करने के लिए होती है। जो भाषा-बोली जहाँ सरल हो उसका उपयोग करना ठीक है किन्तु किसी भाषा का राजनीतिक दृष्टिकोण से विरोध करना उचित नहीं है। आखिर हिंदी से उन्हें इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? केन्द्र ने सभी स्थानीय भाषा का सम्मान करते हुए उसे शिक्षा में उपयोग हेतु नीति बनाई है। उसने किसी भाषा को अस्मान नहीं की है, फिर उससे इतना परहेज क्यों जताया जा रहा है? स्टालिन अपनी संकुचित चुनावी राजनीति के लिए भले ही हिंदी-विरोध की रणनीति अपनायें, पर तमिलनाडु के आम लोग किसी प्रकार भी हिंदी-विरोधी नहीं हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आज भी तमिलनाडु समेत पूरे दक्षिण भारत में सक्रिय है और हजारों तमिल नौजवान बहुत प्रेम से हिंदी भाषा सीख रहे हैं। स्टालिन की संकुचित नीति तमिलनाडु को देश की मुख्यधारा से अलग कर सकती है। - शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

अमानवीयता की पराकाष्ठा

अमानवीयता की पराकाष्ठा है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हादसे में घायल एक वृद्ध की एमएम हॉस्पिटल में उपचार के अभाव में मौत हो गई। मरीज के परिजन इलाज के लिए अग्रिम रुपए जमा नहीं कर पाए थे। इससे डॉक्टर और उसके स्टाफ ने उपचार शुरू नहीं किया और स्वजनों के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने अस्पताल संचालक पर केस दर्ज कर लिया है, वहीं सीएमएचओ ने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। निजी अस्पतालों की मनमानी व अमानवीयता की यह कोई पहली खबर नहीं है। इसके पहले भी रुपए न मिलने के लिए ऐसी कई अमानवीय व संवेदनहीन खबरें आती रही हैं। -हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन

तलाक के बढ़ते मामले

हाल के वर्षों में तलाक के मामलों में वृद्धि ने समाज के सभी वर्गों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़े-बड़े सेलेब्रिटीज भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तलाक के बढ़ते मामलों से यह तौ साफ हो जाता है कि केवल धन, दौलत शोहरत और बाहरी स्थिति से जीवन में सुख और संतुष्टि नहीं मिल सकती। एक स्थिर और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए सबसे जरूरी है आपसी समझ, परस्पर विश्वास और भावनात्मक समर्थन। आजकल भले ही लोग बाहरी सफ़लता को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अंत में मानसिक और भावनात्मक संतुलन ही जीवन में असली सुख लाता है। पहले जहाँ विवाह को एक दीर्घकालिक यात्रा और पारिवारिक ज़िम्मेदारी माना जाता था, वहीं अब लोग जल्दी-जल्दी अपने रिश्तों को खत्म करने में संकोच नहीं कर रहे। लोग अब अपने जीवनसाथी की संतुष्टि से ज्यादा अपनी स्वतंत्रता और सुख को तलाश में रहते हैं, जिससे कई बार संबंधों में खटास आ जाती है। इससे बचने के लिए रिश्तों को आपसी समझ के आधार पर संजोना जरूरी हो गया है। -नितित रावत, फिरोज़ाबाद

